लीगल ऑडिट

इस वित्तीय वर्ष के दौरान सभी 71 पात्र खातों में लीगल ऑडिट किया गया।

स्टॉक ऑडिट

इस वित्तीय वर्ष के दौरान 14 पात्र खातों में स्टॉक ऑडिट किया गया।

आई एस ऑडिट

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कुछ शाखाओं का आई एस ऑडिट करवाया गया।

प्रशासनिक इकाइयों का आंतरिक निरीक्षण

प्रधान कार्यालय और समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों का इस वर्ष के दौरान आन्तरिक निरीक्षण किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड लेखा परीक्षा समिति का गठन भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार द्वारा नामांकित निदेशकों को शामिल कर किया गया है। समिति की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक द्वारा की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गयी।

नाबार्ड निरीक्षण

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 (6) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा दिनांक 31.03.2025 की वित्तीय स्थिति पर बैंक का अंकेक्षण किया गया है। उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट (दिनांक 11.12.2025) की आख्या दिनांक 16.02.2026 को नाबार्ड को प्रस्तुत की जा चुकी है।

प्रबंधन लेखा परीक्षा

बैंक का प्रबंधन लेखा परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 16.06.2025 से 21.06.2025 तक किया गया। रिपोर्ट का समापन निर्धारित समय में किया गया।

बैंक की पॉलिसी संरचना

बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने एवं निरन्तरता बनाये रखने हेतु एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की गई है। दिनांक 31.03.2026 की तिथि में हमारे बैंक की निम्नलिखित नीतियां विधिवत रूप से बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित/ समीक्षा की गई है।

नीतियों की सूची:–

1. ऋण नीति
2. स्वर्ण आभूषणों के विरूद्ध ऋण नीति
3. सिबिल नीति
4. कोलेटरल/क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति
5. एएमएच रूपरेखा नीति
6. एनपीए प्रबंधन
7. सतर्कता नीति
8. धोखाधड़ी प्रबंधन नीति
9. Whistle Blower नीति
10. जांच एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए नीति
11. आंतरिक लेखा नीति
12. समवर्ती लेखा नीति
13. अनुपालना लेखा नीति
14. निवेश नीति
15. केवाईसी/एएमएल नीति
16. अनआदरित चैक एवं इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली नीति
17. मूल्यह्रास नीति
18. अभिलेख अवधारण नीति
19. ई–अपशिष्ट नीति
20. डीईएएफ नीति
21. परिसर नीति
22. शिकायत प्रबंधन नीति
23. अनुपालना नीति
24. प्रशिक्षण नीति
25. स्थानान्तरण नीति
26. अवकाश नीति
27. मेडिकल इन्श्योरेंस नीति
28. मानव संसाधन नीति (मित्रा समिति की सिफारिश पर)
29. वकीलों की नियुक्ति के लिए नीति
30. शिकायत एवं निवारण नीति
31. बीसी नीति
32. जोखिम प्रबंधन नीति
33. आस्ति दायित्व प्रबंधन नीति
34. आईसीएएपी
35. मुआवजा नीति
36. आउटसोर्सिग नीति
37. ग्राहक मूल्य वृद्धि एवं तृतीय पक्ष उत्पाद (क्रास सेलिंग) नीति
38. आईएस सुरक्षा नीति
39. आईटी नीति
40. आईएस लेखा नीति
41. मोबाईल बैंकिग नीति
42. साइबर नीति

43. क्रय नीति
44. इंटरनेट बैंकिग नीति
45. एटीएम परिचालन नीति
46. परिसर किराया नीति
47. व्यापार निरंतरता और आपदा प्रबंधन नीति
48. बैंक जमा नीति
49. शाखा भ्रमण नीति
50. बोर्ड लेखा समिति नीति
51. सीआईसी की सदस्यता
52. एनपीए की प्रणाली जेनरेशन नीति
53. भुगतान एवं निपटान प्रणाली
54. बैंकिग लोकपाल नीति
55. रोकड़ प्रबंधन नीति
56. अनुपालना विभाग
57. निरीक्षण निष्कर्ष की अनुपालना
58. विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालना
59. वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधान
60. आईबीपीसी एवं पीएसएलसी
61. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति
62. एमएसएमई पुनर्वास नीति
63. बीएसबीडीए नीति
64. समझौता नीति
65. चैक संग्रहण नीति
66. व्यवसायिक कोर्स के लिये इंटर्नशिप नीति
67. नकली नोट का पता लगाने की नीति
68. ग्राहक अधिकार नीति
69. अचल संपति नीति
70. स्टाफ जवाबदेही नीति
71. डॉर-स्टैप बैंकिंग नीति
72. पूरक ऑडिट नीति
73. क्रेडिट ऑडिट नीति
74. कानूनी ऑडिट नीति
75. सेफ डिपॉसिट/लॉकर नीति
76. पूंजी प्रबंधन नीति
77. स्टॉक ऑडिट नीति
78. प्रबंधन ऑडिट नीति
79. साइबर संकट प्रबंधन योजना (Cyber Crisis Management Plan)

जोखिम प्रबंधन

यूजीबी के पास विभिन्न प्रकार के जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति मौजूद है।

जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) की अध्यक्षता में त्रैमासिक अंतराल पर सभी विभागों के सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाता है। जोखिम प्रबंधन समिति विभागवार विभिन्न जोखिमों का आंकलन और पहचान करती है और प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति तैयार करती है। कार्यवाही की आगे समीक्षा बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम हेतु कार्यवाही की गई है:

1. तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम: बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता समिति (ALCO समिति) है, जो तरलता की स्थिति और ब्याज दर की समीक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है। बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एएलएम नीति भी तैयार की है और नियमित रूप से ALCO/बोर्ड को तरलता पैरामीटर और ब्याज दर परिदृश्य पेश कर रहा है। बैंक ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बैंकिंग अस्थिरता को देखते हुए बैंक की तरलता की स्थिति का भी आंकलन किया है और बैंक ने तरलता और बाजार जोखिम को संतोषजनक पाया है।

2. परिचालन जोखिम: पिछले वित्तीय वर्ष की तरह, यूजीबी ने सभी शाखाओं में आरसीएसए (जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन अभ्यास) के माध्यम से परिचालन जोखिम को पहचानने और कम करने की प्रक्रिया फिर से पूरी की।

3. क्रेडिट जोखिम: यूजीबी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण और वसूली नीति है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बर्ड-लखनऊ, एसबीआईआरबी-हैदराबाद, सीएबी पुणे, नाबार्ड आदि जैसे अन्य बाहरी संस्थानों से प्रशिक्षण के अलावा, इन हाउस ट्रेनिंग सिस्टम यानी यूजीबी लर्निंग सेंटर के माध्यम से क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अधिकारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया है। कृषि अग्रिमों के लिए एसबीआईआरबी, हैदराबाद के सहयोग से यूजीबीएलसी द्वारा दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

4. अनुपालन जोखिम: यूजीबी के पास प्रभावी ऑडिट नीति लागू है। बैंक शाखाओं में नियमित आरएफआईए ऑडिट और समवर्ती ऑडिट आयोजित कर रहा है।

5. बाहरी पर्यावरण जोखिम: उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसका बैंक के समग्र व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे क्रेडिट और परिचालन जोखिम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा को भी खतरा हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, यूजीबी ने प्रभावी बिजनेस निरंतरता योजना के माध्यम से ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों के मामले में सभी शाखाओं में निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास शुरू किया है।

नाबार्ड के दिशा-निर्देशों पर बैंक द्वारा विभिन्न जोखिमों जैसे-तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम की पहचान, विश्लेषण एवं कमी तनाव-परीक्षण फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इसी के साथ क्रेडिट एवं संचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए विशेष नीतियां जारी की गयी हैं।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलों को सुदृढ़ करते हुए विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया। बैंक ने नई शाखाओं एवं ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP) की स्थापना के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार किया, जिससे अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

CSP नेटवर्क को नवीनतम एंड्राइड तकनीक पर आधारित POS M-ATM मशीन से सुसज्जित किया गया, जिससे सेवा की दक्षता एवं ग्राहक सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सतत जागरूकता कार्यक्रमों एवं वित्तीय समावेशन अभियानों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रसार तथा वित्तीय साक्षरता को भी प्रोत्साहन मिला।

इन पहलों के परिणामस्वरूप बैंक एक डिजिटल रूप से सशक्त एवं समावेशी बैंकिंग मॉडल की ओर अग्रसर हुआ है, जो शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मध्य की दूरी को प्रभावी रूप से कम कर रहा है।

CSP नेटवर्क की प्रगति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्राहक सेवा केंद्र वित्तीय समावेशन के एक सशक्त स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आए हैं। सभी प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र में निहित अपार संभावनाओं को दर्शाती है।

1. लेन-देन में वृद्धि

डिजिटल एवं एजेंट-आधारित बैंकिंग की ओर बढ़ते रुझान के परिणामस्वरूप लेनदेन की मात्रा एवं मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

- संख्या : 16.33 लाख लेन-देन (वर्ष-दर-वर्ष 60% वृद्धि)
- मूल्य : ₹ 594.57 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 69% वृद्धि)

यह वृद्धि CSP मॉडल पर बढ़ते विश्वास एवं नवीनतम POS M-ATM की दक्षता को दर्शाती है।

2. प्रधानमन्त्री जनधन खाते

CSP नेटवर्क औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में नए ग्राहकों को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है

- कुल खाते: 42,021 प्रधानमन्त्री जनधन खाते CSP चैनल के माध्यम से खोले गए ।
- योगदान: बैंक द्वारा वित्तिय वर्ष के दौरान खोले गए कुल प्रधानमन्त्री जनधन खातों में से 60% योगदान CSP का रहा है ।

3. सामाजिक सुरक्षा एवं सूक्ष्म बीमा कवरेज

बैंक ने सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार हेतु CSP नेटवर्क का प्रभावी उपयोग जारी रखा हैं । CSP चैनल के माध्यम से कुल नामांकन -

- **प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना :** 21,775
- **प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना :** 20,225
- **अटल पेंशन योजना :** 5,998

आगामी वित्तीय वर्ष में बैंक का लक्ष्य CSP के माध्यम से इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र जनसंख्या का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है।

4. वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता पहल

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में CSP ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । CSP द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 700 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए तथा व्यापक घर-घर संपर्क अभियान चलाए गए । इन पहलों का मुख्य उद्देश्य था-

- ग्रामीण ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग एवं AEPS के उपयोग के प्रति शिक्षित करना
- साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता एवं सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार को प्रोत्साहित करना
- औपचारिक ऋण एवं दीर्घकालिक बचत के लाभों के प्रति प्रेरित करना

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ-

बैंक ने वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति

बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY)- के नामांकन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। इन प्रयासों के माध्यम से बैंक ने समाज के लिए वित्तीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :

- नए नामांकन: 1,18,662 (पिछले वर्ष की तुलना में 34% वृद्धि)
- कुल कवरेज: अब तक कुल 7,01,531 व्यक्तियों को किफायती दुर्घटना बीमा के अंतर्गत शामिल किया गया है

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :

- नए नामांकन: 81,659 (वर्ष-दर-वर्ष 27% वृद्धि)
- कुल कवरेज: 3,62,838 व्यक्तियों का जीवन बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया है

अटल पेंशन योजना :

- नए नामांकन: 30,214 (निर्धारित लक्ष्य 29,100 के विरुद्ध 104% उपलब्धि)
- कुल कवरेज: 2,03,610 नागरिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान की गई है

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया

वार्षिक उपलब्धि पुरस्कार

- वार्षिक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार
- "Winning Wednesday" के अंतर्गत बहु-पुरस्कार
- APY प्रीमियर लीग के अंतर्गत "APY Excellence Cup"

बैंक इन महत्वपूर्ण योजनाओं की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने हेतु सतत प्रयासरत है, जिससे प्रत्येक परिवार को औपचारिक वित्तीय सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके।

CSP नेटवर्क का तकनीकी उन्नयन: एंड्रॉइड आधारित माइक्रो एटीएम

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के डिजिटल रूपांतरण में अग्रिम पंक्ति के सेवा प्रदाताओं का तकनीकी उन्नयन एक प्रमुख कारक रहा है। एंड्रॉइड आधारित माइक्रो एटीएम ने पारंपरिक डेस्कटॉप-आधारित बैंकिंग से आगे बढ़ते हुए एक सशक्त एवं बहुउद्देशीय बैंकिंग मॉडल की स्थापना की है। इस डिवाइस ने उत्तराखंड राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को नई दिशा प्रदान की है।

- **संचालनात्मक मानक :**

  नवीन हैंड-हेल्ड डिवाइस CSP संचालन के लिए नया मानक स्थापित कर रहे है, जिससे ग्राहकों के द्वार पर अथवा दूरस्थ क्षेत्रो में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना संभव हुआ है।

- **दक्षता में वृद्धि :**

  एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की पोर्टेबिलिटी एवं सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस के कारण लेनदेन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही CSP के आय में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

  एंड्रॉइड आधारित माइक्रो एटीएम केवल लेनदेन डिवाइस नहीं हैं, बल्कि ये पूर्णत: कार्यात्मक "मिनी शाखाएं" हैं, जिनमें विभिन्न डिजिटल सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध है

- **कोर बैंकिंग एकीकरण :**

  AEPS लेनदेन (निकासी/जमा/हस्तांतरण), Rupay कार्ड आधारित लेनदेन, स्वयं सहायता समूह लेनदेन तथा ग्रीन पिन जनरेशन की सुविधा ।

- **खाता नियोजन :**

  तत्काल खाता खोलने की सुविधा के साथ-साथ सावधि जमा एवं आवर्ती जमा खोलने की भी सुविधा ।

- **डिजिटल सीडिंग :**

  रियल-टाइम मोबाइल सीडिंग एवं AEPS, जिससे ग्राहकों को डिजिटल अलर्ट एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ा जा सके।

- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज :**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में त्वरित नामांकन हेतु सरल मॉड्यूल उपलब्ध।

इन पहलों के माध्यम से बैंक एक सुदृढ़, तकनीक रूप से सक्षम एवं समावेशी बैंकिंग तंत्र के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से समुदायों का सशक्तिकरण

उत्तराखंड के भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता, प्रभावी वित्तीय समावेशन की आधारशिला के रूप में कार्य करती है।

बैंक ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का ज्ञान भी आवश्यक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बहुआयामी जन-जागरूकता रणनीति को अपनाया।

- **डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविर :**

  शाखाओं द्वारा CSPs की सक्रिय सहभागिता के साथ 500 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें डिजिटल बैंकिंग एवं सुरक्षित वित्तीय व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया।

- **RE-KYC जागरूकता अभियान:**

  1,000 से अधिक शिविरों के माध्यम से ग्राहकों को केवाईसी/री-केवाईसी के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इन प्रयासों को भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता ने और अधिक सुदृढ़ किया।

- **नुक्कड़ नाटक पहल:**

सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वित्तीय जागरूकता बढ़ाने हेतु 13 नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके द्वारा बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों को सरल एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुँचाया गया।

बीमा दावों का कुशल निपटान: सामाजिक सुरक्षा के वादों को किया साकार

किसी भी सामाजिक सुरक्षा ढांचे की वास्तविक प्रभावशीलता उसके दावों के निपटान की गति एवं दक्षता से आंकी जाती है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभों के समयबद्ध वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, ताकि आवश्यकता की घड़ी में प्रभावित परिवारों को त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित दावों का निपटान किया -

- पीएमजेजेबीवाई : 295 दावों का निपटान, कुल राशि ₹ 5.90 करोड़
- पीएमएसबीवाई : 81 दावों का निपटान, कुल राशि ₹1.62 करोड़

इन प्रयासों के माध्यम से बैंक ने प्रभावित परिवारों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है।

वित्तीय साक्षरता वैन के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार

बैंक ने वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु 10 वित्तीय साक्षरता वाहनों के माध्यम से राज्यभर में जागरूकता अभियानों को प्रभावी रूप से संचालित किया है। इन वाहनों के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एवं UPI जैसे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ये वाहन विशेष रूप से चारधाम एवं हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख तीर्थ मार्गो के साथ-साथ औली एवं धनोल्टी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं, जहां दूरस्थ एवं अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में बैंकिंग जागरूकता का सफल विस्तार किया गया।

इस पहल को माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा कृषाली चौक शाखा के उद्घाटन अवसर पर सराहना प्राप्त हुई, जहां बैंक द्वारा एटीएम वैन का प्रदर्शन भी किया गया।

तीर्थयात्रियों, पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पहल की सफलता को दर्शाती है, जिसने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मॉडल CSP पहल: अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं का सशक्तिकरण

बैंक ने CSP की पहचान एवं व्यावसायिक मानकों को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान "मॉडल CSP सेंटर" की अवधारणा प्रारंभ की। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP) को उच्च दृश्यता वाले, ग्राहक-केंद्रित "मिनी बैंकिंग यूनिट" के रूप में विकसित करना है, जो आधुनिक बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरिद्वार जनपद में प्रथम मॉडल CSP सेंटर का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया, जो सुल्तानपुर शाखा से संबद्ध है। इस केंद्र का संचालन श्री सुभाष सिंह द्वारा किया जा रहा है, जो बैंक के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले CSP में से एक हैं तथा पिछले एक दशक से अधिक समय से बैंक से जुड़े हुए हैं।

बैंक की परिकल्पना प्रत्येक जनपद में एक मॉडल CSP सेंटर स्थापित करने की है, जिससे CSP आउटलेट्स को सुसज्जित एवं सशक्त सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सके। ये केंद्र "मिनी बैंकिंग यूनिट" के रूप में कार्य करते हुए ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण एवं विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक की परिकल्पना को प्रभावी एवं सटीक रूप से क्रियान्वित करने हेतु सभी हितधारकों के व्यापक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई। बैंक कर्मचारियों एवं सीएसपी के ज्ञान एवं कौशल को एकीकृत करते हुए एक सशक्त एवं समन्वित कार्यबल तैयार किया गया, जो बिना किसी ज्ञान अंतराल के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्पित है।

- **कर्मचारी प्रशिक्षण (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) :**

  प्रधान कार्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रमुख विषयों के साथ-साथ CSP संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया।

- **वेबिनार:**

  नियमित वेबिनार के माध्यम से नवीनतम दिशा-निर्देश एवं वित्तीय समावेशन के महत्व की जानकारी कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों तक पहुंचाई गई।

- **CSP प्रशिक्षण (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) :**

  CSP के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य ज्ञान -अंतराल को समाप्त करना था। इन कार्यक्रमों में ऋण उत्पादों, अनुपालन आवश्यकताओं एवं संचालन दक्षता पर विशेष फोकस रखा गया।

इन पहलों के माध्यम से बैंक ने कर्मचारियों एवं CSP की दक्षता, जागरूकता एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की है, जिससे वित्तीय समावेशन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिला है।

वित्तीय समावेशन एवं CSP के सुदृढ़ीकरण में नाबार्ड का सहयोग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड द्वारा CSP चैनल को सशक्त बनाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनायें प्रारंभ की गई। नाबार्ड के "ENGAGE" पोर्टल के माध्यम से दावा प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल एवं सुगम हो गई है, जिससे पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि हुई है।

बैंक ने नाबार्ड समर्थित कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से लागू किया तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत निम्न अनुदान प्राप्त किया -

- **नुक्कड़ नाटक:** ₹ 1.53 लाख
- **डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** ₹ 17.75 लाख
- **सीएसपी माइक्रो एटीएम सहायता:** ₹ 9.50 लाख
- **संशोधित सीएसपी प्रोत्साहन योजना:** ₹ 82.35 लाख

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को नाबार्ड से कुल ₹ 1.97 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

इन निधियों के माध्यम से आधुनिक MATM तकनीक द्वारा CSP नेटवर्क को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। साथ ही, डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (DFLP) एवं नुक्कड़ नाटक जैसी व्यापक पहलों के माध्यम से राज्यभर में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

डिजिटल उत्कृष्टता तथा सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में अग्रसर (वित्तीय वर्ष 2025-26)

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी डिजिटल क्षमताओं को और मजबूत किया। इस दिशा में ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा इन-हाउस तकनीकी समाधानों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे सुरक्षित, कुशल एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

I- डिजिटल बैंकिंग एवं ग्राहक सुविधा में वृद्धि

वर्ष के दौरान बैंक ने डिजिटल सेवाओं के दायरे को बढ़ाने तथा मौजूदा प्लेटफॉर्म की उपयोगिता में सुधार करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिससे ग्राहक अधिक सेवाओं का डिजिटल माध्यम से लाभ उठा सकें।

मुख्य पहलें:

- मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग में नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई, जिनमें री-केवाईसी, नामांकन अपडेट तथा सरलीकृत IMPS फंड ट्रांसफर शामिल हैं, जिससे लेनदेन अधिक तेज एवं विश्वसनीय हुआ।
- डिजिटल अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 40,069 नए मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण, 6,125 इंटरनेट बैंकिंग (रिटेल) पंजीकरण, 2,537 इंटरनेट बैंकिंग (कॉरपोरेट) पंजीकरण, तथा 89,199 एटीएम कार्ड जारी किए गए।
- वीडियो केवाईसी को खाता खोलने एवं री-केवाईसी हेतु विस्तारित किया गया, जिससे ग्राहक दूरस्थ रूप से खाता खोलने एवं केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,177 खाते VKYC के माध्यम से खोले गए, जिससे कागजी कार्यवाही कम हुई तथा सुविधा बढ़ी।

- बैंक जनसेतु प्लेटफॉर्म (नाबार्ड की पहल) पर लाइव हुआ, जिसके माध्यम से गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, मुद्रा ऋण, व्यवसाय ऋण, वाहन ऋण एवं शिक्षा ऋण सहित विभिन्न ऋणों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त बैंक e-KCC पोर्टल पर भी लाइव हुआ।
- मौजूदा डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया गया, जिनमें ई-डिपॉजिट, चेक संबंधी सेवाएँ (जारी करना, स्थिति जांच, भुगतान रोकना), एटीएमकार्ड सेवाएँ जैसे ऑनलाइन कार्ड अनुरोध, कार्ड ब्लॉक/सक्रियकरण, लेनदेन सीमा प्रबंधन, AEPS सक्षम/अक्षम, कॉन्टैक्टलेस कार्ड एवं ग्रीन पिन जनरेशन शामिल हैं।
- लालढांग शाखा (जिला हरिद्वार) का उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से बैंक में सफलतापूर्वक विलय किया गया, जिसे ग्राहकों की सेवाओं में बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से संपन्न किया गया तथा शाखा को पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया।

II- साइबर सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण

वर्ष के दौरान बैंक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने तथा डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु कई लक्षित पहलें कीं।

मुख्य उपाय:

- बैंक की वेबसाइट एवं आधिकारिक ईमेल प्रणाली को नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षित डोमेन "ukgb.bank.in" पर स्थानांतरित किया गया।
- सिस्टम एवं डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (NAC) तथा सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (SFTP) लागू किए गए।
- एक्टिव डायरेक्टरी आधारित एक्सेस कंट्रोल को मजबूत किया गया तथा End-of-Life (EOL) सिस्टम समाप्त किए गए।
- सभी शाखाओं में SD-WAN लागू किया गया, जिससे सुरक्षा एवं नेटवर्क प्रदर्शन दोनों में सुधार हुआ।
- प्रॉक्सी एवं फायरवॉल आर्किटेक्चर के माध्यम से नियंत्रित इंटरनेट एक्सेस लागू किया गया।
- नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट, अनुपालन समीक्षा एवं फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किए गए।
- DPDP अधिनियम संबंधी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- वेबसाइट, शाखाओं, सोशल मीडिया, एसएमएस एवं अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा व्यापक ग्राहक जागरूकता अभियान चलाए गए।
- ₹ 50.00 करोड़ का साइबर बीमा कवरेज अपनाया गया।
- एंडपॉइंट सुरक्षा एवं उपयोगकर्ता एक्सेस नियंत्रण को और मजबूत किया गया।

बैंक को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा "Cyber Security Team of the Year के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

III. इन-हाउस प्रौद्योगिकी विकास एवं परिचालन दक्षता

बैंक ने निगरानी, परिचालन नियंत्रण तथा प्रक्रिया दक्षता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी इन-हाउस तकनीकी क्षमताओं का निरंतर विस्तार किया।

मुख्य विकास:

- **UGB My Bank Portal** को एक केंद्रीकृत मंच के रूप में सुदृढ़ किया गया, जहाँ परिपत्र, नीतियाँ, एमआईएस, रिपोर्ट एवं अन्य आंतरिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **Branch Profile (Version 2)** तथा **Daily Branch Reporting Portal (DBPR Version 2)** को मजबूत किया गया, जिससे निगरानी, रिपोर्टिंग एवं प्रदर्शन मूल्यांकन में सुधार हुआ।
- **UGB Sahaj Connect Portal** का विकास एवं उपयोग **SMA/NPA** निगरानी तथा संरचित अनुवर्ती कार्यवाही (**Follow&up Tracking**) हेतु किया गया।
- **Account Navigator** को और सुदृढ़ किया गया, जिससे एक ही स्क्रीन पर खाते एवं अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।
- **SETU Portal** लागू किया गया, जिससे मानव संसाधन (HR) प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण हुआ तथा कर्मचारी सेवाएँ, संचार एवं प्रदर्शन मूल्यांकन एकीकृत मंच पर संभव हुआ। इसमें शिकायत निवारण एवं कर्मचारी सहभागिता जैसी सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं।
- **CMS (Cash Management System) Portal** लागू किया गया, जिससे निर्धारित सीमाओं के भीतर प्रभावी नकदी प्रबंधन सुनिश्चित हुआ।

- **Interest Subvention Tool** लागू किया गया, जिससे सब्सिडी गणना की प्रक्रिया स्वचालित हुई।
- **Loan Origination System** (**LOS**) को विभिन्न उत्पादों जैसे कार ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, जमा के विरुद्ध ऋण, SHG, संपत्ति के विरुद्ध ऋण तथा SME उत्पादों हेतु लागू किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व से लागू KCC, व्यक्तिगत ऋण एवं स्वर्ण ऋण को भी इसमें सम्मिलित रखा गया।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईटी केंद्रित पहलों ने बैंक की डिजिटल सेवा क्षमता, साइबर सुरक्षा ढाँचे तथा आंतरिक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया। ये प्रयास बैंक की सुरक्षित, कुशल एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण

हम अपने समर्पित कर्मचारियों की टीम के माध्यम से ग्राहकों को श्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्राहकों की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण हेतु बैंक ने बोर्ड अनुमोदित शिकायत निवारण नीति (Grievance Redressal Policy) लागू की है, जिसका उद्देश्य ग्राहक शिकायतों का समाधान करना एवं ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बैंक ने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया है तथा शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने हेतु फॉलो-अप प्रणाली को मजबूत किया गया है।

ग्राहक अपनी शिकायतें प्रधान कार्यालय स्थित शिकायत प्रकोष्ठ (Grievance Cell) को लिखित रूप में, अथवा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के पते एवं संपर्क विवरण सभी शाखाओं में उपलब्ध हैं। सभी शाखाओं द्वारा प्रत्येक तिमाही ग्राहक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया (Feedback) भी दे सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों हेतु बैंक के महाप्रबंधक को प्रधान कार्यालय में "Principal Nodal Officer" नामित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act)

बैंक ने अपने विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है।

शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIO) नामित किया गया है। संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) नामित किया गया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधक (HR) को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIO) नामित किया गया है। मुख्य प्रबंधक (DPD) को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) नामित किया गया है। महाप्रबंधक (प्रशासन) को बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक को 146 RTI आवेदन एवं 21 अपीलें प्राप्त हुई। इनमें से 141 RTI आवेदन एवं 18 अपीलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया। शेष 5 RTI आवेदन एवं 3 अपीलों का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 4 CIC (Central Information Commission) सुनवाईयों में भाग लिया।

30.05.2025 को तृतीय पक्ष के माध्यम से सुओ-मोटो पारदर्शिता ऑडिट संपन्न किया गया।

सतर्कता प्रशासन (Vigilance Administration)

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी संशोधित व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की, जिसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिन्हें माननीय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

इन संशोधनों की प्रमुख विशेषता मौजूदा व्यवस्था का केंद्रीकरण है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने इस नीति के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाने हेतु QR Scanner सुविधा भी प्रारंभ की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में कुल 28 PVC बैठकें आयोजित की गईं। UGBLC में 16 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 456 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कर्मचारियों को निवारक सतर्कता (Preventive Vigilance) के प्रति जागरूक करने तथा दैनिक कार्यों में आवश्यक सावधानी बरतने हेतु नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

महाप्रबंधक (सतर्कता) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 46 शाखाओं का सुओ-मोटो निरीक्षण किया गया।

31.03.2026 तक 41 सुओ-मोटो अनुपालन रिपोर्टों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week)

बैंक ने 27.10.2025 से 02.11.2025 तक प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सभी शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

इस अवधि के दौरान अनेक शाखाओं द्वारा विद्यालयों एवं ग्राम सभाओं में कार्यशालाएँ एवं शिविर आयोजित किए गए। बैंक द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Contest) का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों एवं आमजन में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2026 को बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (मार्च 2026 में सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के कारण बैंक सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) तथा उनका वर्गीकरण निम्नानुसार है:

पदनाम	कुल सं.	महिला	सामान्य	अनु. जा.	अनु. जनजा.	अ. पि.जा.
अधिकारी श्रेणी V	1	0	1	0	0	0
अधिकारी श्रेणी IV	11	1	7	1	1	2
अधिकारी श्रेणी III	62	8	40	8	6	8
अधिकारी श्रेणी II	208	48	130	31	11	36
अधिकारी श्रेणी I	464	122	250	86	32	96
कार्यालय सहायक	374	114	232	71	13	58
कार्यालय परिचर	18	5	13	3	0	2
कुल	**1138**	**298**	**673**	**200**	**63**	**202**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 42 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं जिनमें 2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है। 28 कर्मचारियों के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है तथा 1 कर्मचारी की वर्ष के दौरान मृत्यु हो गई है।

भर्तियाँ

दिनांक 31.03.2025 को बैंक व्यवसाय के आधार पर बैंक द्वारा विभिन्न ग्रेडों में कर्मचारियों की भर्ती की गयी है जिसमें सामान्य बैंकिग के साथ साथ विशेषज्ञता वाले स्केल द्वितीय व स्केल तृतीय अधिकारियों की पार्श्व भर्ती शामिल है।

ग्रेड	वर्ष के दौरान भर्तियों की संख्या
कार्यालय परिचर	00
कार्यालय सहायक	94
अधिकारी श्रेणी I	81
अधिकारी श्रेणी II	07
अधिकारी श्रेणी III	02

सभी नियुक्तियां आईबीपीएस द्वारा संचालित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा सम्पन्न की गयी हैं।

पदोन्नतियाँ

कर्मचारियों को त्वरित पदोन्नति देने की बैंक की नीति को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2025 के व्यवसाय एवं जनशक्ति आकलन के आधार पर पदोन्नतियाँ की गई हैं और विभिन्न संवर्गो में 81 कर्मचारियों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया:

S.No.	Promoted to	No. of Posts
1	अधिकारी श्रेणी- V	00
2	अधिकारी श्रेणी - IV	03
3	अधिकारी श्रेणी -III	13
4	अधिकारी श्रेणी -II	30
5	अधिकारी श्रेणी -I	35
6	कार्यालय सहायक	00
	Total	81

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया है, ऐसे कार्मिकों को लिखित परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेने से पूर्व बेहतर तैयारी करने में सक्षम बनाया है।

प्रशिक्षण-स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र

वर्ष के दौरान बैंक ने 45 (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 596 स्टाफ सदस्यों (पुनरावर्तकों) सहित को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रतिभागियों में सभी संवर्ग (अधिकारी -376, कार्यालय सहायक और कार्यालय परिचर -220) शामिल हैं।

कुल 87 अधिकारियों ने 23 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण तथा वेबिनार कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनका आयोजन NABARD/ BIRD (लखनऊ), RBI तथा SBIRB (हैदराबाद) जैसे प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषयों में शामिल थे- केवाईसी-एएमएल, एएलएम, आरटीआई अधिनियम, ट्रेजरी प्रबंधन, व्यवसाय विकास ऋण मूल्यांकन, अनुपालन, एनपीए प्रबंधन आदि।

बैंक की प्रशिक्षण नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

बैंक के इन हाउस लर्निंग सेन्टर में नव नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और उन्हें पुनः प्रशिक्षित करने व सभी क्षेत्रों में दक्ष करने के लिये लगातार काम किया जा रहा है ताकि उन्हें दैनिक कार्यो के सफल संचालन के लिये कुशल बनाया जा सके।

बैंक महिला कर्मचारियों के हितों पर निरन्तर ध्यान दे रही है। वे कुल कार्यबल का लगभग 26 प्रतिशत हैं। बैंक ने संस्था के भीतर सशक्तिकरण को वढावा देने के लिये कई कदम उठाये हैं। वर्ष के दौरान 132 महिला कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति और आंतरिक शिकायत समिति –

बैंक के कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करके बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल भी बनाया है। हमने सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। और प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने और आरओ स्तर पर हल की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई है। हम दोनों लिंगों के कर्मचारियों को स्वस्थ और अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

कर्मचारी कल्याण के उपाय

मेडिक्लेम पालिसी

भारत सरकार के पत्र संख्या F81/2015-RRB दिनांक 20.10.2016 के संदर्भ में बैंक द्वारा दसवें एवं ग्यारहवें द्विपक्षीय वेतन समझौते की शर्तो के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु चिकित्सा बीमा योजना लागू की गयी है। इस योजना में कर्मचारी + पति या पत्नी + आश्रित बच्चे + 02 आश्रित माता पिता/सास–ससुर हेतु क्रमशः अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये क्रमशः रु० 4 लाख व रु० 3 लाख का चिकित्सा बीमा उपलब्ध है। आकस्मिक चिकित्सीय खर्चो के लिए रु० 20 लाख का बफर कोटा रखा गया है। इस योजना में अस्पताल में परेशानी मुक्त तुरन्त भर्ती की सुविधा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा के द्वारा अस्पताल भर्ती दावों के निपटान को बहुत आसान बना दिया गया है, जिससे प्रशासनिक समय की काफी बचत होती है। इस योजना में बीमा राशि का 10 प्रतिशत तक बगैर भर्ती हुए घर पर रहकर उपचार में हुए व्यय भी शामिल है।

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और संस्थान के प्रति वफादारी का निर्माण करने के लिये निम्नलिखित बीमा राशि के साथ सभी कर्मचारी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंर्तगत आच्छादित हैं।

क्रमांक	पद	बीमित राशि
1	अधिकारी	रु० 125 लाख
2	कार्यालय सहायक	रु० 100 लाख
3	कार्यालय परिचर	रु० 100 लाख

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (कोविड–19)

महामारी कोविड–19 के कठिन समय के दौरान कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और संस्थान के प्रति निष्ठा का निर्माण करने के लिये निम्नलिखित बीमा राशि के साथ सभी कर्मचारी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंर्तगत आच्छादित हैं।

क्रमांक	पद	बीमित राशि
1	अधिकारी	रु० 20 लाख
2	कार्यालय सहायक	रु० 10 लाख
3	कार्यालय परिचर	रु० 10 लाख

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण फंड

बैंक द्वारा ग्रेच्युटी की अनुमानित आवश्यकता हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये हैं। बैंक को 31.03.2026 में रु0 36.16 करोड़ ग्रेच्युटी हेतु व रु० 40.46 करोड़ अवकाश नकदीकरण हेतु कुल कॉर्पस है।

पेंशन

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, हमने अपने बैंक में सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 2024 (संशोधन) के माध्यम से पेंशन योजना लागू की है। वर्तमान में बैंक द्वारा 396 सामान्य पेंशनभोगियों तथा 96 पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

बैंक एनपीएस कॉर्पोरेट पीओपी (Point of Presence) बन गया है। अब कर्मचारियों के मासिक एनपीएस अंशदान अपलोड करने तथा अन्य गैर–वित्तीय लेनदेन सहित सभी एनपीएस संबंधी कार्य बैंक द्वारा स्वयं किए जा रहे हैं, तथा इसके लिए कर्मचारियों से कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाता है।

औद्योगिक संबंध

प्रबंधन तन्त्र, अधिकारी संगठन व कर्मचारी संघ द्वारा स्टाफ सदस्यों के कल्याण तथा व्यवसाय वृद्धि के लिये मिलकर काम किया गया है। वर्ष के दौरान उत्पन्न हुये मुद्दों को सौहार्दपूर्ण समाधान द्वारा निस्तारित किया गया है। वर्ष के दौरान सहयोगपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा।

अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का कल्याण

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध बनाये रखा गया है और भर्तियों व पदोन्नति आदि के सभी पहलुओं में सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण के लिये कल्याण संघों के प्रतिनिधियों एवं उनके जन सम्पर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की गई हैं।

बैंक द्वारा कर्मचारियों के मनोबल और उत्साह को बनाये रखने के लिये सभी कदम उठाए हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान

बैंक द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि को ही कर दिया जाता है। सेवानिवृत्ति की तिथि को भुगतान करने के लिये सभी औपचारिकताऐं पूरी करने के लिये सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व ही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है।

एक्सग्रेसिया का भुगतान

बैंक द्वारा भारत सरकार के अधिसूचना संख्या F.20/5/2003-RRB दिनांक 09.06.2006 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है, जिसमें मृतक व गम्भीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाता है।

अनुकम्पा नियुक्ति

बैंक ने 06.03.2019 को भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आरआरबी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मॉडल योजना लागू की है, जो उनकी अधिसूचना संख्याः एफ.एन.ओ. 7/38/2014-आरआरबी दिनांक 31.12.2018 में निहित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में डीएफएस आदेश क्रमांक एफ.एनओ. 11/19/2023-दि.14.09.2023 बैंक ने 06.03.2014 से भारत सरकार के निर्देशानुसार आरआरबी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित मॉडल योजना लागू की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 05 आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है।

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण करने के लिये कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कर्मचारी सहभागिता

बैंक सकारात्मक कार्य संस्कृति, पारस्परिक विश्वास तथा कर्मचारियों में अपनत्व की भावना को बढ़ावा देने हेतु कर्मचारी सहभागिता (Employee Engagement) पर विशेष बल देता है।

इस उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न संरचित एवं अनौपचारिक सहभागिता पहलें आयोजित की जाती हैं, जिनमें SETU पहल के अंतर्गत विभिन्न मंच शामिल हैं, जैसे, NAVCHETNA- FROM SELF BELIEF TO SOCIETY CHANGE कर्मचारियों में प्रेरणा एवं मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु, SIDHI BAAT कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच संरचित एवं पारदर्शी संवाद के लिए एक मंच के रूप में, CHAMAK बैंक में प्रतिभा, नवाचार एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को पहचान और प्रोत्साहन देने हेतु।

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा दीपावली, होली, हरेला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे महत्वपूर्ण पर्वों एवं अवसरों का आयोजन किया जाता है तथा क्रिकेट प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला) जैसी खेल गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य टीमवर्क, समावेशिता, कर्मचारी कल्याण एवं कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना है।

इन पहलों का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा कर्मचारियों और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां

यूजीबी स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एसजी कारकों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यावरण संबंधी ज़िम्मेदारी

यूजीबी सतत विकास लक्ष्यों तथा हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी बैंकिंग प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक कृषि, संबद्ध गतिविधियों एवं स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल लघु उद्यमों को ऋण प्रदान कर सतत आजीविका को बढ़ावा देता है।

यूजीबी डिजिटल बैंकिंग पहलों के माध्यम से अपने परिचालन में पर्यावरणीय विचारों को समाहित करता है, जिससे कागज के उपयोग में कमी आती है तथा कार्बन फुटप्रिंट न्यूनतम होता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण प्रयासों तथा समुदाय आधारित जलवायु अनुकूलन (Climate Resilience) पहलों जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन प्रदान करता है।

एक जलवायु-संवेदनशील राज्य में कार्यरत होने के कारण, यूजीबी पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

सामाजिक योगदान

अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक ने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विभिन्न शाखाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिससे कर्मचारियों एवं समुदाय के बीच स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर अपनाने के प्रति जागरूकता और प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे सामुदायिक सेवा एवं जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन: सुदृढ़ किया।

The Bank celebrated the Harela Festival by participating in Plantation drives, promoting environmental sustainability and social responsibility.

बैंक ने उत्तरकाशी के धराली गाँव में क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) की घटना के दौरान प्रभावित समुदायों के सहयोग में भी सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभावित परिवारों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी शाखा द्वारा SDRF बेस कैंप (उत्तरकाशी) में प्रभावित लोगों को आवश्यक राशन सामग्री एवं ताजी सब्जियों का वितरण किया गया।

यह राहत सामग्री स्थानीय प्रशासन एवं SDRF टीम के समन्वय से उपलब्ध कराई गई, जिससे जरूरतमंद लोगों तक सहायता समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पहुँचाई जा सके।

यह प्रयास प्राकृतिक आपदा के समय सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहयोग के प्रति हमारे बैंक की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शी नियम और नियंत्रण बनाता है, नेतृत्व का मार्गदर्शन करता है, और शेयरधारकों, निदेशकों, प्रबंधन और कर्मचारियों के हितों को संरेखित करता है। बैंक अपने हितधारकों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन को पारदर्शी बनाने में विश्वास करता है।

निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक मण्डल का गठन उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, नाबार्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होते है। दिनांक 31.03.2025 तक कुल नौ निदेशकों में से दो गैर सरकारी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित नहीं किये गये हैं। कलैण्डर वर्ष के दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए है। बैंक निवर्तमान निदेशकों के मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद व्यक्त करता है एवं नये निदेशकों का स्वागत करता है।

पूर्व निदेशक	नियुक्त की दिनांक	नव नियुक्त निदेशक
श्री राजीव कुमार वर्मा उप महाप्रबन्धक सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, मुम्बई	01/05/2025	श्री वी. शिवा कुमार मुख्य महाप्रबंधक सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, मुम्बई
श्री वी. शिवा कुमार मुख्य महाप्रबंधक सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, मुम्बई	14/07/2025	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़ महाप्रबंधक सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, मुम्बई
श्री अभय गुप्ता सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून	01/07/2025	श्री परमदीप सिंह सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून
श्री निर्मल कुमार उपमहाप्रबंधक नाबार्ड, देहरादून	14/08/2025	श्री भूपेन्द्र कुमावत उप महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
रिक्त	01/10/2025	श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड के निदेशकों का सक्षिप्त विवरण

नाम	पदनाम	योग्यता
श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	बी.एससी., एमबीए (बैंकिग व फाइनेन्स)
श्री प्रकाश चन्द्र बरोड	महाप्रबंधक, सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कार्पोरेट आफिस, मुम्बई	बी.कॉम., बी.एड., बैंकिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, CAIIB
श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक (बीएण्डओ) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-3,न्यू कैण्ट रोड देहरादून	बी.ए डेटा बेस प्रबंधन में डिप्लोमा व्यावसायिक वित्त में डिप्लोमा
श्री परमदीप सिंह	सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून	बी.एससी., एम.ए. (अर्थशास्त्र)
श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक नाबार्ड, देहरादून	बी.ए, CAIIB
श्रीमती अनुराधा पाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखण्ड सरकार	बी.टेक.
श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	एमएससी
श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी	अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	बी.ए

निदेशक मण्डल की बैठक

निदेशक मण्डल की बैठक के नियमों के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छः बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा त्रैमास में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाती है। भारत सरकार के राजपत्र में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान कुल 06 बैठकें आयोजित की गयी।

आयोजित बैठकों की संख्या	06
बैठकों की तिथि	21.03.2025, 29.04.2025, 30.06.2025, 01.09.2025, 1 5.10.2025, 15.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	6	6
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	6	5
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	2	2
4	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	3	2
6	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	6	3
7	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	1	1
8	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	3	2
9	श्री परमदीप सिंह	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	3	3
10	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	3	2
11	श्रीमती अनुराधा पाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखण्ड सरकार	6	2
12	श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी	अवर सचिव (डीएफएस), भारत सरकार	2	2

लेखा परीक्षा समिति

आंतरिक पर्यवेक्षी प्रणाली की निगरानी के लिये दिनांक 19.12.2012 को आयोजित पहली बोर्ड बैठक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था ,जो नियामक/पर्यवेक्षी संस्थानों को दी गयी सूचना की शुद्धता सुनिश्चित करती है। लेखा परीक्षा समिति के पांच सदस्य हैं और लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें कैलेण्डर वर्ष 2025 में आयोजित की गयी।

आयोजित बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 15.12.2025, 29.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
5	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
6	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
7	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	4	4
8	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
9	श्री परमदीप सिंहसहायक	महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2
10	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक नाबार्ड, देहरादून	2	1
11	श्रीमती अनुराधा पाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखण्ड सरकार	4	3
12	श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी	अवर सचिव (डीएफएस), भारत सरकार	1	1

धोखाधड़ी निगरानी समिति

धोखाधड़ी निगरानी समिति का मुख्य कार्य धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिये आंतरिक नीति को तैयार करना है। दिनांक 19.12.2012 को पहली बोर्ड बैठक में फ्राड मानिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया था, इसके पांच सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 15.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
5	श्री अभय गुप्तासहायक	महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
6	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	4	4
7	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
8	श्री परमदीप सिंहसहायक	महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2

20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी निगरानी समिति

नाबार्ड परिपत्र संख्या NB-DoS-CFMC/2927/P&80/2016&17 दिनांक 06.12.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी समिति का गठन बोर्ड की बैठक दिनांक 19.10.2020 में किया गया था, इसके पांच सदस्य हैं। दिनांक 01.09.2025 को आयोजित 83वीं निदेशक मंडल बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार, 20 लाख से अधिक राशि के धोखाधड़ी मामलों हेतु गठित पृथक Fraud Monitoring Committee का विलय Fraud Monitoring Committee में कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	02
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
5	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
6	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	4	4
7	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
8	श्री परमदीप सिंह	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2

ग्राहक सेवा समिति

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015–16/59 डीबीआर नंबर लेग.बीसी.21/09.07.006/2015–16 दिनांक 01.07.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राहक सेवा समिति का गठन दिनांक 22.03.2021 को बोर्ड की बैठक में किया गया था और इसके चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 15.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
4	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
5	श्री परमदीप सिंह	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2
6	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	2	1
7	श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी	अवर सचिव (डीएफएस), भारत सरकार	1	1

जोखिम प्रबंधन समिति

दिनांक 22.03.2021 को बोर्ड की बैठक में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया और इसमें चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 29.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
6	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
7	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	2	1

एनपीए निगरानी समिति

गैर निष्पादित आस्तियों की निगरानी के लिये दिनांक 29.08.2016 को आयोजित की 25वीं बोर्ड बैठक में तीन सदस्यों वाली एनपीए निगरानी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 29.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
3	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
5	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
6	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	2	1

विशेष पुनरीक्षण समिति

कर्मचारियों की सेवा का पुनरीक्षण करने के लिए 72वीं बोर्ड बैठक, जो कि दिनांक 01.11.2023 को आयोजित की गयी थी, में तीन सदस्यीय विशेष पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 29.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
6	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
7	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	2	1
8	श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी	अवर सचिव (डीएफएस), भारत सरकार	1	1

आईटी उपसमिति

आईटी उपसमिति, जिसमें चार सदस्य शामिल हैं, को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे की निगरानी हेतु 27.06.2024 को आयोजित 76वीं निदेशक मंडल की बैठक में गठित किया गया।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04
बैठकों की तिथि	05.02.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 15.12.2025

वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
3	श्री वी. शिवा कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	1
4	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
6	श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़	महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुशंगी विभाग), भारतीय स्टेट बैंक	2	2
7	श्री परमदीप सिंह	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2
8	श्री भूपेन्द्र कुमावत	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून	2	1

संचार के माध्यम

बैंक अपने सभी हितधारकों को पूर्ण एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विश्वास रखता है। बैंक हिन्दी व अंग्रेजी में दो प्रमुख समाचार पत्रों में अपना वार्षिक विवरण प्रकाशित कर रहा है। बैंक का वित्तीय विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह सभी हितधारकों को मुद्रित रुप में प्रदान किया जाता है।

स्वीकृतियाँ (Acknowledgements)

निदेशक मंडल हमारे सभी हितधारकों, साझेदारों एवं ग्राहकों के प्रति गहन आभार व्यक्त करता है, जिनके सहयोग और विश्वास ने हमारी वृद्धि और प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके सहयोग एवं समर्थन हमारी निरंतर सफलता के लिए अमूल्य है।

निदेशक मंडल प्रायोजक बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके मार्गदर्शन, सहयोग और दूरदर्शी रणनीति ने हमारी यात्रा को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बोर्ड, श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई, श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक, एसबीआई, श्री अतुल श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर, श्री प्रकाश चन्द्र बरोड़, महाप्रबंधक (आरआरबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर एवं एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई के एएंडएस विभाग के सभी टीम सदस्यों के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट समर्थन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने हमारे बैंक को सतत सफलता की ओर अग्रसर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उनके समर्पण, विशेषज्ञता एवं हमारे साझा लक्ष्यों की सतत् प्राप्ति हेतु प्रयासों की सराहना करते हैं।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता है, जिनके निरंतर विश्वास और निष्ठा ने हमें सेवाएं देने का गौरव प्रदान किया है। हम आपके विश्वास पर खरा उतरने और आपकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

अंततः, निदेशक मंडल हमारे समर्पित कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता है। आपका परिश्रम, उत्साह और हमारे मिशन एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा ही हमारी सफलता की नींव है। हम आपके योगदान और समर्पण को गहराई से मान्यता देते हैं और उसका उच्च मूल्यांकन करते हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से
उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

(हरि हर पटनायक)
अध्यक्ष

UTTARAKHAND GRAMIN BANK

PERFORMANCE OF THE BANK : AT A GLANCE

(Amount in Thousands)

S. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
I	KEY PERFORMANCE INDICATORS					
1	No. of Districts in service area	13	13	13	13	13
2	No. of Branches	299	291	290	288	286
	a) Rural	227	220	219	217	216
	b) Semi-Urban	42	41	41	41	41
	c) Urban	30	30	30	30	29
	d) Metropolitan	0	0	0	0	0
3	Total Staff (Excl. Sponsor Bank Staff)	1138	1025	999	1087	1049
	Out of Which, Officers	746	665	627	643	613
4	Deposits	91188684	84704937	78336215	71177595	64855343
	Growth %	7.65%	8.13%	10.06%	9.75%	8.00%
5	Borrowings	4311200	2844105	1909802	1002335	854324
	Growth %	51.58%	48.92%	90.54%	17.32%	-22.63%
6	Gross Loans & Advances O/S	52840605	45779526	37476356	31473983	27908147
	Growth %	15.42%	22.16%	19.07%	12.78%	7.49%
	Of 6 above, Loans to Priority Sector	32345943	26417579	21337896	18706420	17498102
	Of 6 above, Loans to SC/ST	3009567	3757456	3437340	3219514	3093099
	Of 6 above, Loans to SF/MF/AL	6348901	5160229	4307009	3225956	2968356
	Of 6 above, Loans to Minorities		19405571587688127716910936991042270			
7	C.D. Ratio	57.95%	54.05%	47.84%	44.22%	42.96%
8	Investment Outstanding (excluding TDRs)	39283581	36712501	37224150	34541482	32783267
	Growth %	7.00%	-1.37%	7.77%	5.36%	13.07%
	i. SLR Investment	38249991	35489262	36205109	33795736	32233626
	ii. Non SLR Investment (excluding TDRs)	1033590	1223238	1019041	745746	549641
	CA balances with Bank	284323	329684	501667	321364	316836
	TDR balances with Bank	8546087	9055821	8579572	7833889	6803484
II	AVERAGE					
1	Average Deposits	87316993	80475777	73992220	67129865	61675287
	Growth %	8.50%	8.76%	10.22%	8.84%	7.55%
2	Average Borrowings	3705184	2144602	1225169	938763	987152
	Growth %	72.77%	75.05%	30.51%	-4.90%	-15.09%
3	Average Gross Loans & Advances O/S	48680826	39955015	33307744	28453714	25937773
	Growth %	21.84%	19.96%	17.06%	9.70%	5.98%

4	Average Investment (excl. TDRs)	37878322	36948607	35526696	33665564	31815008
	Growth %	2.52%	4.00%	5.53%	5.82%	13.47%
	Average SLR Investment	36708401	35888060	34590263	33063133	31110752
	Average Non SLR Investment (excl. TDRs)	1169921	1060547	936433	602431	704256
	Average Investment as % to Average Deposits	10.31%	13.25%	55.44%	50.15%	51.58%
5	Average Working Funds	101121759	90207230	81379916	72876092	66018286
III	LOANS DISBURSED					
1	Total Loans disbursed during the year	30713687	29280537	24684695	20131676	16293456
	of 1 above, Loans to Priority Sector	17431574	15983157	12022893	9235883	7868931
	of 1 above, Loans to Non-Target Group	13282113	13297379	12661802	10895793	8424525
	of 1 above, Loans to SC/ST	2179222	1995044	1887363	1789444	1519253
	of 1 above, Loans to SF/MF/Agriculture labourers	4591033	3953044	3206844	2180811	1688925
IV	PRODUCTIVITY					
1	Per Branch	481703	448400	399354	356429	324726
	Per Employee	126564	127302	115928	94089	88114
V	RECOVERY PERFORMANCE					
1	Total (as on 30th June 2023)					
	Demand	12141101	10671788	9819254	8099855	7193591
	Recovery	10766770	9200663	8304407	6554416	5703264
	Overdues	1374331	1471126	1514848	1545439	1490327
	Recovery %	88.68%	86.21%	84.57%	80.92%	79.28%
(i)	Farm Sector					
	Demand	2321254	1786852	1823386	1550027	1653010
	Recovery	1625159	1059511	1118495	870471	1020473
	Overdues	696095	727341	704891	679556	632537
	Recovery %	70.01%	59.29%	61.34%	56.16%	61.73%
(ii)	Non-Farm Sector					
	Demand	9819847	8884936	7995868	6549828	5540581
	Recovery	9141611	8141152	7185912	5683945	4682791
	Overdues	678236	743785	809957	865883	857790
	Recovery %	93.09%	91.63%	89.87%	86.78%	84.52%
VI	ASSET CLASSIFICATION					
1	Standard Assets	51216365	44290968	35924394	29755053	25896503
	Sub-Standard Assets	451606	269164	258894	262914	453726
	Doubtful Assets	1129827	1185087	1257163	1436496	1545494
	Loss Assets	42807	34307	35905	19520	12424
	Total Gross Advances	52840605	45779526	37476356	31473983	27908147
2	Standard Asset as % to Gross Advances	96.93%	96.75%	95.86%	94.54%	92.79%

	Gross NPA %	3.07%	3.25%	4.14%	5.46%	7.21%
	Net NPA %	0.00%	0.00%	0.02%	1.50%	3.04%
VII	PROFITABILITY ANALYSIS					
1	Interest Paid					
	On Deposits	3722624	3483358	3108918	2575741	2391588
	On Borrowings	212804	140037	71153	43198	44472
2	Salary & Allowances to Employees	1818934	1823311	1686027	1360642	1460429
3	Pension Payment & Provision	154334	177342	50161	653242	666621
4	Other Operating Expenses	1021580	808146	650299	664724	577011
5	Provisions made during the Year					
	Against NPAs	128387	8111	253	167441	110072
	Other Provisions	221271	91844	328057	54134	59749
6	Interest earned					
	On Loans & Advances	4485967	3727747	3164460	2736771	2380444
	On TDRs with Banks	626939	704758	614325	430977	286252
	On SLR Investments	2689408	2630974	2547602	2402146	2270817
	On Non-SLR Investments	62875	62581	59276	45619	41338
7	Misc. Income	541252	445985	386447	343114	401459
8	Profit/Loss					
	Profit before Tax	1126505	1039896	877243	439505	70369
	Profit after Tax	837884	781144	752555	437796	68196
VIII	OTHER INFORMATION					
1	Share Capital Deposit Received*	0	0	4	0	0
2	D.I.C.G.C.					
	Claims Settled Cumulative	0	0	0	0	0
	Claims received but pending for adjustment	0	0	0	0	0
	Claims pending with the Corporation	0	0	0	0	0
3	Cumulative Provision					
	Against NPAs	1129507	1128532	1162417	1258772	1186766
	Against other intangible assets	0	0	0	0	0
4	Derecognised income					
	During the year	0	0	0	0	0
	Cumulative	0	0	0	0	0
5	Loans written off during the year					
	No. of A/cs	1939	525	993	1164	67
	Amount (excluding notional intt.)	127412	42016	100493	104264	8396
6	Accumulated Losses	0	0	0	0	0
7	Reserves	3820350	2982465	2201321	1448766	1010970

* Share application money received from GOI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT 2025-26

We are pleased to present the fourteenth report on the business and operations of the Bank, accompanied by the Audited Statement of Accounts for the financial year ending on March 31, 2026.

Overview of Indian economy

The outbreak of the conflict in West Asia has led to severe disruption of global supply chains. This poses an unprecedented challenge for the global economy – higher prices and lower global growth. Real gross domestic product (GDP) is estimated to grow by 7.6 per cent (y-o-y) during the FY 2025-26, as per the Second Advance Estimates (SAE) of the new GDP series (base year 2022-23).

Purchasing Manager Index (PMI) manufacturing dropped to 53.9 (lowest in four years) and PMI services dropped to 57.5 in the month of March 2026, due to West Asia conflicts.

Looking ahead, elevated energy and other commodity prices coupled with supply shock due to disruptions in the Strait of Hormuz would act as a drag on domestic production in 2026-27.

Taking all these factors into consideration and on the assumption that the adverse impact of the conflict would remain contained in the near term, real GDP growth for 2026-27 is projected at 6.9 per cent, with Q1 at 6.8 per cent; Q2 at 6.7 per cent; Q3 at 7.0 per cent; and Q4 at 7.2 per cent. CPI inflation for 2026-27 is projected to be at 4.6 per cent with Q1 at 4.0 per cent; Q2 at 4.4 per cent; Q3 at 5.2 per cent; and Q4 at 4.7 per cent.

RBI has cut the repo rate by 100 basis points during FY 2025-26 to reach 5.25% in December 2025 and remained unchanged till April 2026 meeting.

Uttarakhand Economy

Uttarkhand per capita income is expected at Rs. 2,73,921 with an increase of 9.25% in FY 2025-26 as against last year at Rs. 2,50,736 and India's per capita income is estimated at Rs. 219575 in FY 2025-26 at 6.9% YoY growth.

The growth rate of Uttarakhand's GSDP is estimated (last estimate) to grow at 6.44% in 2024-25, and projected at 7.23% for FY 2025-26. State fiscal deficit is estimated at 3.62% & primary deficit at 1.61% of GSDP for FY 2025-26 as against 2.74 % fiscal deficit & 0.83% primary deficit in previous FY.

9.59%, 39.95%, and 50.46% contribution to the state's economy by Primary sector, Secondary and Tertiary sector respectively is expected in 2025-26 (Source: Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Uttarakhand retrieved from des.uk.gov.in/economic-survey/). Agriculture showed a negative growth of 4% and constitute 34% of total Primary Sector, Livestock constitutes 27%, Forestry & logging constitutes 27% and Fishing& aquaculture constitutes only 0.54% of total Primary sector in FY 2025-26. 2.79% of total budget is allocated to agriculture in FY 2025-26

It is evident that Uttarakhand's economy is a Tourism driven Economy as known as Dev Bhoomi (Land of the Gods). Total 51.04 Lakhs pilgrims has worshiped during 2025 in Chardham (16.60 lakhs in Badrinath, 17.68 laks in Kedarnath, 7.58 lakhs in Gangotri, 6.44 lakhs in Yamunotri & 2.74 Lakhs in Hemkund Sahib).

Uttarakhand emerged as a significant destination for investments in manufacturing industry, tourism & infrastructure. Delhi–Dehradun Expressway has recently opened in April 2026, which will give a boost to MSME & service industry.

Overview of Banking Industry in Uttarakhand

There are total 35 Banks in Uttarakhand having 2622 branches as on 30.09.2025. State has total 35 Banks comprising 12 PSBs, 1 RRB (UGB), 15 Private Banks, 5 Small Finance Banks and Co-operative Banks (1 State Cooperative Bank, 10 District Central Co-operative Banks). Besides, there was one branch of UP Gramin Bank in Haridwar District, which is amalgamated in Uttarakhand Gramin Bank on 22-02-2026.

Total deposits of all the Banks in the state stood at Rs. 252059 crore as on 30.09.2025 at 10.54% YoY growth. Total advances of all the Banks in the State is Rs. 134458 crore (excluding RIDF) as on 30.09.2025 at 12.13% YoY growth. The Gross NPA of all Banks in the State is 3.24% as on 30.06.2025.

CD ratio of the state is 54.67% and the CD ratio excluding RIDF is 53% as on 30.09.2025. Agricultural advances contribute 12.90% of total advances and Priority sector advances contribute 52.08% of total advances as on 30.09.2025. MSME advances constitute 28.60% of total advances as on 30.09.2025. (Source: SLBC Book).

New Branch/ Offices

The bank has a presence in all 13 districts of Uttarakhand with a network of 299 branches and 624 Business Correspondents. The bank has opened eight new Branches, one service branch & one Regional Office during the FY 2025-26. The Bank has also acquired one branch Laldhang from Uttar Pradesh Gramin Bank due to presence in State territory. Details of new added branches are given below:

Category	Code	Name	District	Date of opening
Branch	805	Krishali Chowk	Dehradun	29-09-2025
Branch	242	Naugaon khal	Pauri	29-09-2025
Branch	438	Lalpur Nayak	Nainital	29-09-2025
Branch	163	Chamiyala	Tehri Garhwal	29-09-2025
Branch	164	Pipaldali	Tehri Garhwal	31-12-2025
Branch	264	Nandanagar	Chamoli	31-12-2025
Branch	196	Khanpur	Haridwar	29-01-2026
Branch (acquired from UPGB)	197	Laldhang	Haridwar	22-02-2026
Branch	198	Jhabrera	Haridwar	30-03-2026
Regional Office	600	Haridwar	Haridwar	30-03-2026

Business Review

The Bank's business has grown at a rate of 10.38% to reach ₹ 14402.92 crore as on 31 March 2026 as against ₹ 13,048.45 Crore as on 31 March 2025.

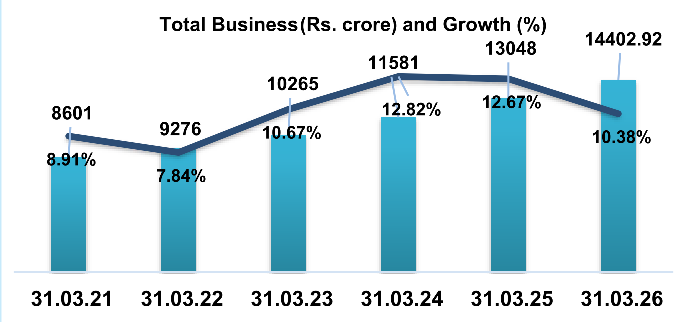

Profit Analysis

The Bank has earned ₹ 147.62 crores operating profit and ₹ 83.79 crores net profit in FY 2025-26 as against ₹ 113.90 crores operating profit and ₹ 78.11 crores net profit in FY 2024-25.

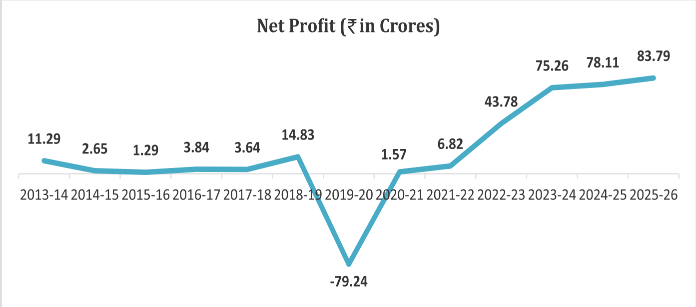

Income and Expenditure

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2025-26	Growth%
Interest Income	712.61	786.52	10.37%
Interest Expenditure	362.34	393.54	8.61%
Other Income	44.60	54.13	21.37%
Operating Expenses	280.88	299.48	6.62%
Operating Profit	113.90	147.62	29.60%
Provisions and Contingencies	10.00	34.97	249.70%
Profit before tax	103.99	112.65	8.33%
Income Tax	25.92	27.65	6.67%
Deferred Tax Asset & Earlier year adjustments	0.05	1.21	2520.00%
Net Profit after tax	78.11	83.79	7.27%

Net Interest Income

Total interest income earned during the year is ₹ 786.52 crores whereas total interest expenditure is at ₹ 393.54 crores. The net interest income has increased by ₹ 42.71 crores to ₹ 392.98 crores during the year vis-à-vis ₹ 350.27 crores in 2023-24.

(₹ in Crore)

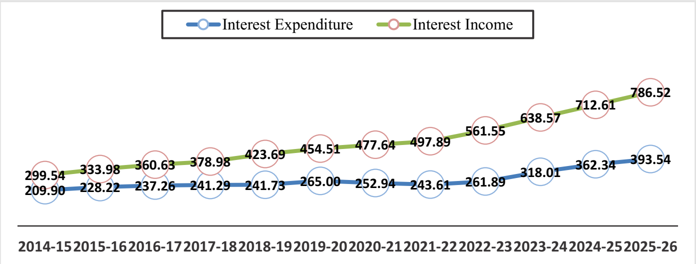

Interest Expenditure

- Interest paid on deposits has increased to ₹ 372.26 Crore from the last FY's figure of ₹ 348.34 Crore by ₹ 23.92 Crore. Cost of deposits decreased by 7 basis points to 4.26% as against 4.33% in 2024-25.
- The average cost of borrowings has reduced from 6.53% in 2024-25 to 5.74% in 2025-26. The Bank has paid ₹ 21.28 Crore towards interest on borrowings (refinance from NABARD and other organizations) during the year as against ₹ 14.00 crores during the previous FY.

(₹ in Crore)

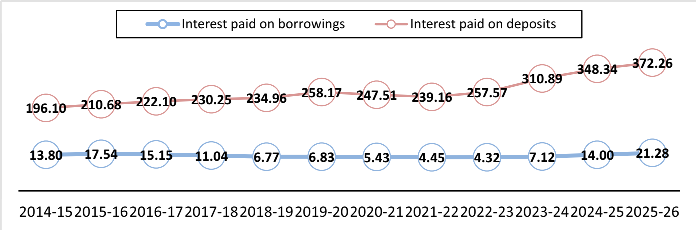

Operating Expenditure

- Operating expenditure has increased by ₹ 18.60 Crore (6.62%) to ₹ 299.48 Crore in 2025-26 from ₹ 280.88 Crore in the previous FY 2024-25.
- Operating expenditure also includes ₹ 15.43 crores contribution/provision towards annual pension liability in FY 2025-26.

Other Income

- Other income increased by Rs. 9.53 crores (21.36%) to Rs. 54.13 crores during 2025-26 from Rs. 44.60 crore during 2024-25. The Bank has earned Rs. 8.97 crore through profit on sale of investment during the FY. Share of non-interest income to total income increased from 5.89% during FY 2024-25 to 6.44% during FY 2025-26.

Interest Income

- Interest income increased from ₹ 712.61 Crore to ₹ 786.52 Crore during the FY 2025-26 with an absolute growth of ₹ 73.91 Crore (@ 10.37%).
- The Bank has earned an interest income of ₹ 448.60 Crore from loans and advances in current fiscal as against ₹ 372.77 Crore in 2024-25 with an increase of ₹ 75.82 Crore (@20.34%).
- The interest income received from investments and term deposits in other Bank has decreased by ₹ 1.91 Crore to reach ₹ 337.92 Crore as against ₹ 339.83 Crore in the previous FY.

(₹ in Crore)

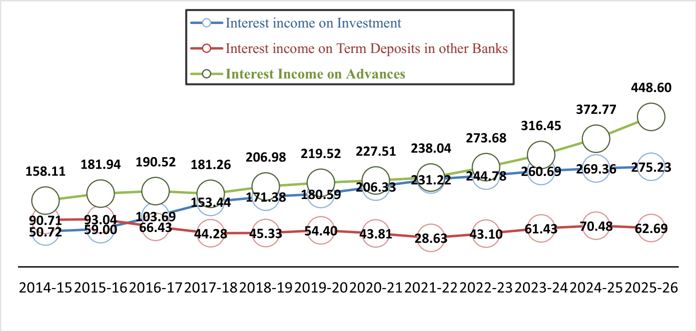

Provision for NPAs:

- The Bank has made a provision of ₹ 12.84 crore on NPAs and Rs. 2.27 crore for standard assets during FY 2024-25.

(₹ in Crore)

Assets	2024-25		2025-26	
	O/s	Provisions	O/s	Provisions
Standard	4429.10	14.77	5121.64	17.04
Sub-Standard	26.92	4.16	45.16	7.23
Doubtful	118.51	105.26	112.98	101.45
Loss	3.43	3.43	4.28	4.27
Total	**4577.95**	**127.63**	**5284.06**	**129.99**

In addition to the above, Bank has made a floating provision of of Rs. 7.06 crore during FY 2025-26.

Ratio Analysis

S. No.	Ratios	Units	2024-25	2025-26	Change
			Amt / Ratio		
1	Yield on advances	%	9.33	9.22	-0.11
2	Yield on investments	%	7.29	7.27	-0.02
3	Cost of deposits	%	4.33	4.26	-0.07
4	Cost of borrowings	%	6.53	5.74	-0.79
5	Avg. cost of funds	%	4.30	4.15	-0.15
6	Avg. return of funds	%	8.46	8.30	-0.16
7	Cost of management	%	3.11	2.96	-0.15
8	Misc. Income as % to Working Funds	%	0.49	0.54	0.05
9	Net Margin	%	1.15	1.11	-0.04
10	Financial Margin	%	4.16	4.15	-0.01
11	Risk Cost	%	0.11	0.35	0.24
12	Return on Assets	%	0.87	0.83	-0.04
13	Return on Equity	%	16.21	14.80	-1.41
14	Expenses Ratio	%	71.13	66.98	-4.15
15	Gross NPAs	₹ Crores	148.86	162.42	13.56
16	Net NPAs	₹ Crores	0.00	0.00	0
17	% Provisions to gross NPAs	%	100	100	0
18	Gross NPAs to advances	%	3.25	3.07	-0.18
19	Net NPAs to advances	%	0.00	0.00	0
20	CRAR	%	12.63	13.85	1.22

Balance Sheet Size

The balance sheet size increased from ₹ 9546.76 crores as on 31.03.2025 to Rs. 10419.62 crore as on 31.03.2026 with an increase of ₹ 872.86 crores as compare to ₹ 809.81 Crores increase in the previous year.

Share Capital & Reserves

The total authorized capital of the Bank is ₹ 2,000 crore; divided into 2,00,00,00,000 fully paid-up equity shares of ₹ 10 each. The total paid-up share capital of the Bank is ₹ 1,84,26,65,000 (18,42,66,500 shares of ₹ 10 each) as on 31.03.2026. Share capital is contributed by the Central Government, State Bank of India (Sponsor Bank), and State Government in ratio of 50:35:15 respectively.

(Amt in Rs.)

Shareholders	Shareholding %	Total capital as on 31.03.2024
Govt. of India	50%	921,332,500
State Bank of India	35%	644,932,750
Govt. of Uttarakhand	15%	276,399,750
Total		**1,842,665,000**

Net Reserves stood at ₹ 382.03 crores as on 31.03.2026 as against ₹ 298.25 Crores as on 31.03.2025.

CRAR

The Capital Adequacy Ratio marginally increased to 13.85% at the end of the financial year compared to 12.63% as on 31.03.2025. Details of Tier-I, Tier-II Capital, Reserves and computation of CRAR are given below:

(₹ in Crore)

	Capital	2024-25	2025-26
1	Tier-I		
	a. Paid up Capital including share capital deposits	184.27	184.27
	Less: Accumulated Losses/ Intangible Assets	0.71	0.00
	b. Statutory Reserves & Surplus	84.48	101.24
	c. Capital Reserves	0.00	0.00
	d. Other Reserves	82.10	82.10
	e. Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	0.00	0.00
	f. Surplus in P&L	88.16	154.72
	Total reserves (b+c+d+e+f)	254.30	338.06
	Total Tier-I Capital	438.29	522.33
2	Tier-II		
	a. Undisclosed Reserves	0.00	0.00
	b. Revaluation Reserves	0.00	0.00
	c. General Provisions & Reserves	26.53	22.52
	d. Investment fluctuations Reserves/Fund	43.51	43.98
	Total Tier-II Capital	70.04	66.49
	Grand Total (Tier I + Tier II)	508.33	588.82
3	a. Adjusted value of funded risk assets i.e. balance sheet items	4015.39	4243.50

	b. Adjusted value of non-funded risk assets i.e. off- balance sheet items	10.02	8.05
	c. Total risk-weighted assets (a+b) d. Percentage of Capital (Tier-I + Tier II) to Risk Weighted Assets	4025.41 12.63%	4251.54 13.85%

Deposits

Total deposits as on 31.03.2026 stand at ₹ 9118.87 Crore as against ₹ 8470.49 Crore as on 31.03.2025 with a growth rate of 7.65%.

(₹ in Crore)

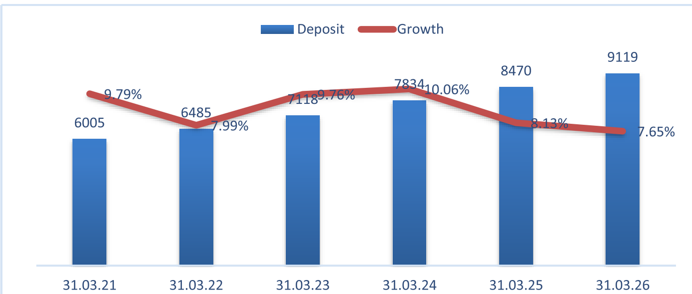

Deposit Mix

CASA deposits grew by ₹ 321.75 Crore at 6.58% to reach ₹ 5213.05 Crore as against ₹ 4891.30 Crore as on 31.03.2025.

Term Deposits grew by ₹ 326.61 Crore to reach a level of 3905.81 Crore at 9.13% growth as against ₹ 3579.20 Crore as on 31.03.2025. The share of CASA Deposits to total deposits decreased from 57.75% as on 31.03.2025 to 57.17% as on 31.03.2026.

(₹ in Crore)

Deposit mix	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Current A/c	151.71	171.02	200.84	214.39
Growth	-2.78	19.31	29.82	13.55
Growth %age	-1.80%	12.73%	17.44%	6.75%
Savings Bank A/c	3988.58	4392.93	4690.46	4998.66
Growth	378.69	404.35	297.53	308.20
Growth %age	10.49%	10.14%	6.77%	6.57%
Total CASA	4140.29	4563.95	4891.29	5213.05
Growth	375.91	423.66	327.34	321.75
Growth %age	9.99%	10.23%	7.17%	6.58%
Term Deposits	2977.47	3269.67	3579.20	3905.81
Growth	256.31	292.20	309.53	326.61
Growth %age	9.42%	9.81%	9.47%	9.13%
Total deposits	7117.76	7833.62	8470.49	9118.87
Growth	632.22	715.86	636.87	648.38
Growth %age	9.75%	10.06%	8.13%	7.65%

DICGC Premium:

The Bank is paying a premium to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in due time regarding deposit insurance.

Borrowings

The total refinance availed in this financial year is ₹ 383.58 crore and aggregate borrowings of the Bank as on 31st March 2026 stood at ₹ 431.12 crore.

BORROWING FROM AGENCIES BY UGB DURING 2023-24 , 2024-25 & 2025-26

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	TYPE	2023-24	O/S 31-03-2024	2024-25	O/S 31-03-2025	2025-26	O/S 31-03-2026
1	NABARD	ST-SAO	116.00	95.00	107.15	107.15	135.00	135.00
2	NABARD	LTCRF/LTNFS	26.00	43.61	30.00	61.61	47.00	91.98
3	NABARD	NRLM	-	-	-	-	-	-
4	NABARD	ST-Others	50.00	50.00	112.00	112.00	150.00	150.00
	NABARD TOTAL		-	188.61	249.15	280.77	332.00	376.98

5	SIDBI	RMSE	-	-	-	-	25.00	25.00
6	SIDBI	MSERS	-	-	-	-	25.00	25.00
	SIDBI TOTAL		-	188.61	249.15	280.77	50.00	50.00
7	NSKFDC	Term Loan	-	-	0.40	0.35	0.32	0.34
8	NHFDC	Term Loan	0.06	0.093	0.12	0.17	0.11	0.23
9	NSTFDC	Term Loan	0.32	0.89	0.51	1.07	0.50	1.26
10	NBCFDC	Term Loan	0.33	0.74	0.35	0.99	0.39	1.23
11	NSFDC	Term Loan	0.67	0.64	0.55	1.06	0.26	1.08

Investments

The total investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 3940.18 Crore as on 31.03.2026 from the previous year's level of ₹ 3671.25 Crore by ₹ 268.93 Crore @ 7.32%. Bank has MTM Losses of ₹ 11.82 Crore on AFS Category of Investment as on 31.03.2026 due to increase in yield as impacted by western disturbances. Modified duration for Govt. Securities including SDL & SSDL is 4.04 years.

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount	% of total investment	% of NDTL
1	SLR	3836.82	97.38%	NA
1.1	AFS	2095.48	54.58%	22.65%
1.2	HTM	1741.34	42.09%	18.82%
2	SSDL	10.01	0.25%	NA
3	Mutual Fund	59.30	1.51%	NA
4	Bonds	34.04	0.86%	NA

CRR and SLR

The Bank has complied with the regulatory requirements for the maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well-laid-down system of assessing the CRR and SLR requirements considering the NDTL. There was no default in the maintenance of adequate balances during the year. The Bank has kept ₹ 276.10 crores in CRR and ₹ 3882.12 crores in SLR as on 31.03.2026.

Bank has ₹ 1741.34 crores of Govt. securities in HTM Category and ₹ 2095.48 crores in AFS category. Bank has earned Interest income of ₹ 268.94 crore during FY 2025-26 from SLR investment. Average Yield on SLR Investment is 7.30% for the FY 2025-26. Bank has earned profit of ₹ 5.65 crore from sale of Govt. Securities during FY 2025-26.

Credit Portfolio

The credit portfolio of the Bank rose by 15.42% to ₹ 5284.06 Crore during the financial year ended on 31.03.2026 from the previous year's level of ₹ 4577.95 Crore, thus showing an absolute growth of ₹ 706.11 Crore. Priority sector advances grew at 22.44% in FY 2025-26 to reach ₹ 3234.59 Crore.

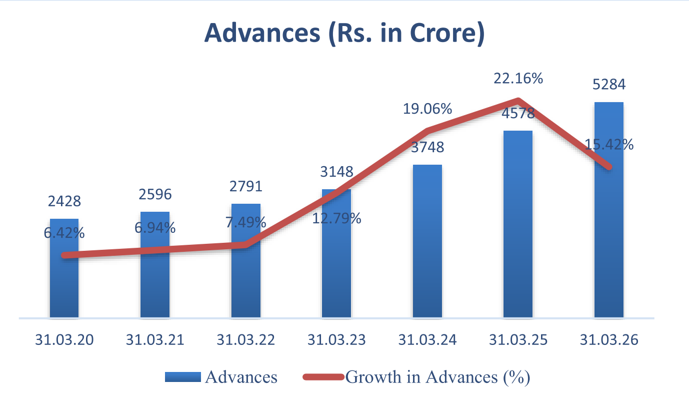

Credit to Agriculture

Total credit to agriculture and allied activities stood at ₹ 818.36 Crore as on 31.03.2026 as against ₹ 695.05 Crore as on 31.03.2025 and recorded a growth of 17.74%. The Bank has disbursed ₹ 597.91 Crore to agriculture sector during CFY as compared to ₹ 535.87 Crore during FY 2024-25.

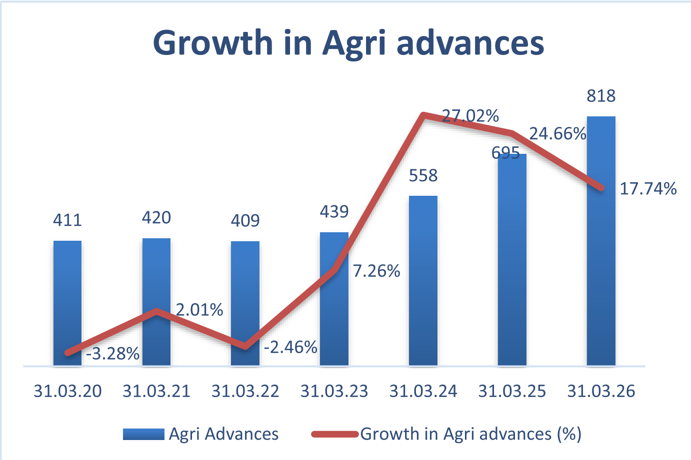

New Agri Product

Bank has also introduced Krishi Udyam Rin scheme for financing Agri enterprises during FY 2025-26.

Crop loans under the Kisan Credit Card

The Bank has made all efforts to disburse Agri-credit through Kisan Credit Cards exploiting the available limited potential to its maximum. We have 43406 KCC accounts as on 31.03.2026 out of which 5553 new KCCs were issued in FY 2025-26. During the FY 2025-26, we have disbursed an amount of ₹ 254.04 Crore to KCC cardholders with a total outstanding of ₹ 380.96 Crores. KCC has achieved 11.47 % YoY growth in FY 2025-26.

Interest Subvention

As per Government of India guidelines, Bank is charging 7% interest rate to all crop loan borrowers up to Rs 3.00 lakhs and accordingly claimed an amount of Rs 18.50 lakhs towards 1.5% interest subvention (Scheme Year 2023-24) and Rs 85.31 lakhs towards 1.5% interest subvention (Scheme Year 2024-25) from GOI during the FY 2025-26.

As per the directives of Government of India, we have passed on the benefit relating to PRI (Prompt Repayment Incentive) of 3% to the tune of Rs 1.67 crore to the KCC holders and claim have been submitted to NABARD accordingly.

Joint Liability Groups (JLGs)

JLG serves as an important tool for augmenting flow of credit to landless farmers cultivating land as tenant farmers and small/marginal farmers and other poor individuals for taking up farm, off-farm and non-farm activities. As on 31.03.2026, bank has a total of 4695 JLGs accounts loan portfolio with the outstanding amount of ₹ 20.12 Crores. During the FY 2025-26, 86 fresh accounts were financed to the tune of ₹ 0.52 crores.

Self Help Groups

The Bank has given special thrust on formation and credit linkage of Self Help Groups with a view of increasing awareness among the rural masses especially the Women's Self Help Groups regarding fulfillment of their urgent credit needs in a better and a cost effective manner. Our Bank has financed 13103 Self Help Groups with an outstanding portfolio of ₹ 175.62 Crore as on 31.03.2026. During the FY 2025-26 Credit Limits worth ₹ 136.69 Crore have been sanctioned to 3248 groups, out of which 3066 groups were under NRLM and 182 groups other than NRLM have been credit linked with the Bank.

DAY National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) - Aajeevika – Interest Subvention Scheme

Our Bank has implemented NRLM Scheme as per the guidelines issued by NABARD. The Mission aims at creating an efficient and effective institutional platform of the rural poor enabling them to increase household income through sustainable livelihood enhancement and improved access to financial services.

Under the Scheme, all Women DAY NRLM SHGs promoted by Central Government or State Government Line Departments or NABARD, which are linked with our Bank, are eligible to avail the benefits of the Scheme. As per the Scheme, Interest Subvention Scheme on Credit to Women SHG during the Year 2025-26 is applicable in all districts of the country. All such Women SHGs in all districts have been extended credit at 7% rate of interest upto 3 Lakhs and Government would subvent at uniform rate of 4.50% per annum. Apart from this, for Loan above 3 lakh and up to 5 lakh Government would subvent at uniform rate of 5%.

Priority Sector Lending

Total outstanding advances of the Bank stood at ₹ 5284.06 crores as on 31.03.2026 and detailed categorization towards Priority Sector, sub-sector achievement as indicated in table below:

Categories	Target	Achievement
Total Priority Sector	75.00	75.73
Agriculture	18.00	18.40
Small and Marginal Farmers	10.00	11.83
Micro Enterprises	7.50	29.50
Weaker Sections	15.00	28.73

Segment wise details is given below:

(₹ in Crore)

S. No.	Segment	2024-25		2025-26	
		No. of A/cs	O/s	No. of A/cs	O/s
1.	Weaker Sections	80035	1184.18	80876	1607.13
2.	Women Borrowers	21979	945.89	23768	1182.54
3.	Minorities	4126	158.77	4391	194.06
4.	SCs/STs	14522	375.75	13923	401.39

Inter Bank Participation Certificates

We have not entered into Inter Bank Participation Certificate (IBPC) this year.

Priority Sector Lending Certificates

According to RBI circular no. RBI/FIDD/2020-21/72 (FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21) dated September 04, 2020, Bank deals in PSLC in FY 2025-26 as mentioned below:

Details of PSLCs Issued/Purchased

S. N.	Particulars	till Period Ended (Rs. crore)			
		30.06.25	30.09.25	31.12.25	31.03.26
1	Total PSLC (1.1+1.2+ 1.3+1.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Of 1, PSLC Agriculture	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Of 1, PSLC SF/MF	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Of 1, PSLC Micro Enterprises	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Of 1, PSLC General	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total PSLC (2.1+2.2+ 2.3+2.4) Purchased	820.00	820.00	820.00	820.00
2.1	Of 2, PSLC Agriculture	170.00	170.00	170.00	170.00
2.2	Of 2, PSLC SF/MF	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Of 2, PSLC Micro Enterprises	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Of 2, PSLC General	650.00	650.00	650.00	650.00

Government Sponsored Schemes

The Bank continues to participate actively in providing assistance under various Govt. Sponsored Schemes.

Position of Government Sponsored Schemes as on 31.03.2026

(₹ in Crore)

Scheme	O/s as on 31.03.2026		Disbursement in 2025-26	
	No.	Amt.	No.	Amt.
DAY - NRLM	12102	167.86	7495	144.24
Veer Chandra Singh Garhwali	221	50.16	74	17.40
PMEGP	2027	53.97	1027	6.08
NULM (SJSY)	674	4.69	169	1.58
MSSY-Solar	481	325.13	407	187.16
MSY	11974	329.18	5918	150.52
HOME STAY	187	33.33	127	9.88
SVANIDHI	374	0.75	259	0.69
PMFME	143	9.58	93	4.42
OTHERS	1622	25.28	339	12.02
Total	**29805**	**999.93**	**15908**	**534.00**

Participation in State Credit Plans

The Bank's participation in State Credit Plans is as under: